ये जीवन है,
उलझेंगे नहीं
तो सुलझेंगे कैसे।
– अज्ञात

लॉकडाउन की दुश्वारियां

दो महीने से ठप पड़ी रेलवे और हवाई सेवा को फिर से शुरू किया जाएगा तो वे अचानक अपनी पुरानी क्षमता से काम नहीं करने लग जाएंगी। इस पूरे तंत्र में किन–किन स्तरों पर किस–किस तरह की समस्याएं आ चुकी हैं इसका अहसास काम आगे बढ़ने के साथ ही हो पाएगा।

नवीन जोशी।

देश में लॉकडाउन की दुश्वारियों से जूझती आबादी को राहत देने के लिए काफी सोच–विचार के बाद स्पेशल ट्रेनें चलाने और घरेलू उड़ानें शुरू करने का फैसला किया गया। इससे जहां–तहां फंसे लोगों के चेहरों पर उम्मीद भरी मुस्कान आई थी। लेकिन अफसोस कि पहले दिन ही देश भर में करीब 630 उड़ानें रद्द कर दी गईं। केवल दिल्ली एयरपोर्ट पर 80 फ्लाइट्स कैंसल हुईं।

मुंबई एयरपोर्ट पर 20 उड़ानें रद्द हुईं। बड़ी संख्या में लोगों को सपरिवार एयरपोर्ट पहुंच कर बैरंग वापस लौटना पड़ा। लॉकडाउन के चलते जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट करीब–करीब बंद हैं तो एयरपोर्ट पहुंचने और फिर वापस लौटने में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रेनें भी कोई बेहतर उदाहरण नहीं साबित हो रहीं। सबसे बुरी गत श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की है। न केवल उनकी दिशा और गंतव्य का कोई ठिकाना नहीं रह गया है बल्कि उनले लेट होते चले जाने की भी कोई सीमा नहीं रह गई है। ये घंटों में नहीं दिनों में लेट हो रही हैं। सूरत से सिवान के लिए चली ट्रेन न जाने कहां–कहां से भटकती हुई दो के बदले नौ दिन में अपने मुकाम तक पहुंची।

खाना और पानी से वंचित यात्रियों का इतनी लंबी यात्रा के दौरान बीमार पड़ना स्वाभाविक है। कुछ मौतों की भी खबरें हैं। जले पर नमक छिड़कने जैसी बात यह कि ऐसी अव्यवस्था के दौरान भी मंत्रियों का ध्यान समस्या को हल करने से ज्यादा विरोधियों को नीचा दिखाने पर है। रेलमंत्री पीयूष गोयल ट्विटर पर यह साबित करने में लगे हैं कि वे तो मुंबई से 200 ट्रेनें रोज चला सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का प्रशासन इतना निकम्मा है कि समय पर यात्रियों की सूची ही नहीं दे रहा।

बहरहाल, सारी कमियों को स्वीकार करते हुए भी इस हकीकत को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि हम एक असाधारण स्थिति का सामना कर रहे हैं। दो महीने से ठप पड़ी रेलवे और हवाई सेवा को फिर से शुरू किया जाएगा तो वे अचानक अपनी पुरानी क्षमता से काम नहीं करने लग जाएंगी। इस पूरे तंत्र में किन–किन स्तरों पर किस–किस तरह की समस्याएं आ चुकी हैं इसका अहसास काम आगे बढ़ने के साथ ही हो पाएगा। और अभी तो इन्हें काम भी एक तिहाई स्टाफ के साथ ही करना पड़ रहा है। हम भूल नहीं सकते कि वायरस से हमारी लड़ाई अभी चल ही रही है, जिसमें हम अभी तक बीमारी का चढ़ान ही देख रहे हैं।

यहां से यह कितना आगे जाएगी और कब अपनी चोटी पर पहुंचेगी, यह भी हमें पता नहीं है। ऐसे में सबके लिए अच्छा यही होगा कि हम न्यूनतम उम्मीदें लेकर अधिकतम सावधानी के साथ आगे बढ़ें। अपने संसाधनों की सीमाओं के साथ–साथ यह भी याद रखें कि हमारा सरकारी तंत्र अभी बहुत ज्यादा दबाव में है। दूसरी तरफ मंत्रियों और आला अफसरों को भी जनता में ज्यादा उम्मीद जगाने से बचना चाहिए और अर्थव्यवस्था खोलने के इस शुरुआती दौर में आपस की छींटाकशी से परहेज करना चाहिए।

शांति के उपकरण

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

मेरे सुबह के ध्यान सत्र में, मैं दुनिया की 'शांति के लिए पुकार' को सुन सकती हूं। न केवल संघर्ष के अंत के लिए बल्कि एक गहरी, आंतरिक स्थिरता और शांति के लिए, जिसे हम उत्पत्ति की स्थिति भी मानते हैं। शांति को ढूंढने के लिए, सबसे पहले हमें अपने आपको शांत रहना सिखाना पड़ेगा, तभी हम शांतिपूर्ण हो पाएंगे। शांतिपूर्ण होने का मतलब है, मन पर नियंत्रण रखना और लगातार चल रहे विचारों को एक ठहराव देना। एक बार हम मन का ध्यान आकर्षित कर लें, फिर हम उसे मौन, एक सच्चे मौन के लिए मना सकते हैं। मौन बिना ध्वनि की अवस्था नहीं है, बल्कि ऐसी अवस्था है जिसमें हमें शांति महसूस होती है और हमारी भलाई के लिए व्यापक जागरूकता मिलती है।

संपादकीय

बड़े बदलाव का दौर

हमने दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में इस सफलता का साक्षात्कार किया है। कोविड–19 के बाद की परिस्थितियों में विश्व बाजार व्यावसायिक तौर–तरीकों में बदलाव का गवाह बनेगा। यह बदलाव निश्चित रूप से डिजिटल संसाधनों की स्वीकार्यता के साथ कार्यदक्षता बढ़ाने और नए अवसरों को सृजित करने के रूप में हमारे समक्ष होगा। रक्षा उत्पादन भी इसी तरह असीमित संभावनाओं से युक्त क्षेत्र है। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है। कुछ महत्वपूर्ण हथियारों और संसाधनों के आयात पर प्रतिबंध ा भी रहेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत अन्य उपायों में तकनीकी और प्रक्रियागत रूप से आने वाली अड़चनों के कारण कंपनी एक्ट के नाम पर उद्यमियों के साथ होने वाली प्रताड़ना को कम करने का प्रयास किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार प्रभावी कदम है, इससे कृषि उत्पादों को विनियमित करने में सहयोग मिलेगा। इसी तरह सार्वजनिक व निजी सहभागिता से नए एयरपोर्ट्स विकसित करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत को एयरक्राफ्ट रख–रखाव का वैश्विक केंद्र बनाने के प्रयास उल्लेखनीय हैं। घरेलू मोर्चे पर स्थानीय आपूर्ति तंत्र को मजबूत कर स्वदेशी वस्तुओं को वैश्विक ब्रांड में बदला जा सकता है। इसका यह तात्पर्य नहीं निकाला जाना चाहिए कि सरकार की नीतियां पूंजीवाद की पैरोकार हैं, अपितु सरकार निजी पूंजी का आर्थिक व सामाजिक समृद्धि के हेतु संवर्धन करना चाहती है।

नीतियों का आवरण स्पष्ट नजर आता था। इसके बाद हमने 90 के दशक में संरचनात्मक आर्थिक सुधारों के जरिए उद्योग नियंत्रित अर्थव्यवस्था से उदारीकरण की ओर कदम बढ़ाया।

समाजवादी आवरण

धर्मेंद्र प्रधान।

स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों के बाद से ही देश ने जनसांख्यिकी, सामाजिक वास्तविकताओं और ढांचागत चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सुधारों से जुड़े कई कदम उठाए। एक दौर वह भी था जब भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता न होने के कारण अपने आपूर्ति तंत्र को व्यवस्थित करने के लिए खाद्यान्न के आयात पर निर्भर था। इस तरह देश ने कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के दौर देखे हैं। यही वजह है कि भारत में विकास के एक ऐसे अभिनव मॉडल की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें सभी 'वाद' के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए देश की चुनौतियों के समाधान के बहुमुखी विकल्प मौजूद हों।

आजादी के बाद भारत के आर्थिक विकास में सरकारों के व्यापक हस्तक्षेप वाली समाजवादी नीतियों का आवरण स्पष्ट नजर आता था। इसके बाद हमने 90 के दशक में संरचनात्मक आर्थिक सुधारों के जरिए उद्योग नियंत्रित अर्थव्यवस्था से उदारीकरण की ओर कदम बढ़ाया। इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रत्येक चरण में आर्थिक नीतियों का उद्देश्य नागरिकों का कल्याण ही था। लेकिन आर्थिक सुधारों के वर्तमान चरण में हम लोक कल्याण और पूंजी

निर्माण के दोहरे लक्ष्य के साथ निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, उसकी सभी नीतियों का उद्देश्य अभावग्रस्त व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना रहा है। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बिजली, रसोई गैस उज्ज्वला, शौचालय, स्वच्छता, आवास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली समेत स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी गई। हालांकि अभी भी देश की बौद्धिक संपदा का प्रभावी उपयोग नीति निर्धारकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती सिर्फ प्रतिभाओं के पलायन को रोकने की नहीं है, बल्कि उद्यम और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाने की भी है।

टाटा समूह की 19वीं से 21वीं सदी की यात्रा का वर्णन करती आर. एम. लाला की पुस्तक 'क्रिएशन ऑफ वेल्थ' में बताया गया है कि निजी क्षेत्र ने किस तरह राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इस समूह ने औपनिवेशिक काल की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हाइड्रो–इलेक्ट्रिक संयंत्र (1920) और एयर इंडिया इंटरनेशनल (1948) की स्थापना की। हमें देश में आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए इस बौद्धिक पूंजी की ताकत को प्रोत्साहित करना होगा।

कोविड–19 खुद में आत्मनिर्भर भारत के अवसरों का संदेश समाहित किए हुए है। हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के जरिए मांग और आपूर्ति तंत्र को मजबूती दी गई है। इस क्रम में ग्रामीण विकास केंद्रित रोजगार गारंटी योजनाओं के द्वारा लोगों के हाथ में सीधे नकदी भी पहुंचाई गई है। यह कदम मांग और आपूर्ति दोनों मोर्चों पर असरदार साबित होगा। सूक्ष्म, लघु और छोटे उद्योगों के पास नकदी का प्रवाह बढ़ेगा तो इसका बड़ा हिस्सा लोगों को होने वाले भुगतान के रूप में सामने आएगा। आर्थिक पैकेज की अंतिम किस्त में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी नई नीति की घोषणा की जिसमें रणनीतिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की सहभागिता के प्रोत्साहन का जिक्र है।

अष्टयोग-5070

	7				4	5
	33	1	23	6	33	
5		2	4			3
	28		27	4	36	
1	2			5		7
6	37	7	38		33	2
		5		3		

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग5069 का हल

1	5	4	3	2	7	6
2	30	7	31	4	34	2
6	3	2	4	5	7	1
5	37	6	33	6	29	3
7	5	3	6	1	2	4
3	30	5	32	7	34	5
4	2	1	6	3	5	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

विद्युत संयंत्रों का संचालन

मोहन। कई गैर रणनीतिक क्षेत्रों में सरकार अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी का विनिवेश करने जा रही है। उदाहरण के लिए भारत ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में 170 मीट्रिक टन थर्मल कोल का आयात किया। इसमें 55 मीट्रिक टन गैर–प्रतिस्थानिक (अन सब्सटीट्यूटेबल) थर्मल कोल अनिवार्य रूप से तटीय बिजली संयंत्रों द्वारा आयातित किए जाते हैं क्योंकि ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों का संचालन आयातित कोयले से ही किया जा सकता है। देखा गया है कि आयातित कोयले के विकल्प के रूप में 115 मीट्रिक टन मिश्रित योग्य उत्पादन सार्वजनिक उपक्रमों (सीआईएल, एसईसीएल, खनिज विकास निगमों) और कमर्शल माइनिंग के तहत निजी कंपनियों द्वारा संभव है। यह कदम लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में मददगार होगा।